



कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका।



झारखण्ड सरकार

Court Compound, Dumka-814101

E-mail- dfodumka@gmail.com/dfo-dumka@gov.in

; Ph. No- 06434-236072

पत्रांक- 2189 दिनांक- 28/6/'18

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, दुमका।

विषय :- NGT कोलकाता में दायर रामलखन सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के विरुद्ध OA-14/2014EZ से संबंधित दुमका वन प्रमंडल अन्तर्गत अतिक्रमित 14.217 हे० वन भूमि पर निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी, आउटडोर स्टेडियम, राज भवन, पुलिस उप निरीक्षक आवास तथा पुलिस लाईन के लिए नियमितिकरण का प्रस्ताव।

प्रसंग :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-674 दिनांक-20.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में दुमका वन प्रमंडल अन्तर्गत अतिक्रमित 14.217 हे० वन भूमि पर निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी, आउटडोर स्टेडियम, राज भवन, पुलिस उप महानिरीक्षक आवास तथा पुलिस लाईन के लिए नियमितिकरण प्रस्ताव हेतु आपत्तियों का निराकरण प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

(Signature) 28/6/18

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
दुमका वन प्रमंडल, दुमका।



कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका।



झारखण्ड सरकार

Court Compound, Dumka-814101

E-mail- dfodumka@gmail.com/dfodumka@gov.in

; Ph. No- 06434-236072

पत्रांक-..... दिनांक-.....

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, दुमका।

विषय :- NGT कोलकाता में दायर रामलखन सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के विरुद्ध OA-14/2014EZ से संबंधित दुमका वन प्रमंडल अन्तर्गत अतिक्रमित 14.217 हे० वन भूमि पर निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी, आउटडोर स्टेडियम, राज भवन, पुलिस उप निरीक्षक आवास तथा पुलिस लाईन के लिए नियमितिकरण का प्रस्ताव।

प्रसंग :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-487 दिनांक-25.4.2018 तथा तथा इस कार्यालय का पत्रांक 2050 दिनांक 15.6.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में दुमका वन प्रमंडल अन्तर्गत अतिक्रमित 14.217 हे० वन भूमि पर निर्मित मजिस्ट्रेट कॉलोनी, आउटडोर स्टेडियम, राज भवन, पुलिस उप महानिरीक्षक आवास तथा पुलिस लाईन के लिए नियमितिकरण प्रस्ताव के Violation में दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी पर की गई कार्रवाई के संबंध में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार टिप्पणी निम्नवत् है:-

- 1 **आउटडोर स्टेडियम-** उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आउटडोर स्टेडियम के अंश-भाग का वन भूमि में अवैध निर्माण माह जुलाई, 1986 में प्रारंभ हुआ था। तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा यह सूचित करते हुए कि वनभूमि के अंश-भाग में स्टेडियम निर्माण के पक्ष में सरकार नहीं है, आदेश निर्गत किया गया कि उक्त भूमि में यथाशीघ्र वनरोपण कर पार्क के रूप में विकसित किया जाय। उपरोक्त के संदर्भ में प्रमंडलीय पत्रांक-731 दिनांक-17.3.1989 द्वारा अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु उपायुक्त, दुमका को पत्र लिखा गया है। उस पत्र में यह भी उद्धृत किया गया है कि आयुक्त, संथाल परगना के बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि स्टेडियम के निर्माण पर रोक लगा दिया जाएगा। तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका ने पत्रांक-916 दिनांक-29.5.1990 द्वारा स्टेडियम को वनभूमि से बाहर करने हेतु अनुरोध किया गया है। पुनः पत्रांक 1375 दिनांक-18.4.2002, 2450 दिनांक-06.10.2005, 1687 दिनांक-17.7.2007, 2751 दिनांक-21.11.2007, 2325 दिनांक-03.8.2016, 2335 दिनांक-04.8.2016, 3232 दिनांक-12.11.2016, 231 दिनांक 18.01.2017, 277 दिनांक 25.01.2017, 417 दिनांक 08.02.2017, 709 दिनांक 04.3.2017 1225 दिनांक 08.4.2017, 1379 दिनांक 27.4.2017 द्वारा आउटडोर स्टेडियम के निर्माण में अतिक्रमित वन भूमि का अपयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव समर्पित करने हेतु पत्र लिखा गया। (छायाप्रति संलग्न)
- 2 **राजभवन-** विदित हो कि पूर्व में उक्त भवन अंग्रेज के समय काल में निर्मित था, जिसका धारणकर्ता का सिर्फ रूप संपरिवर्तित किया गया है। उक्त भवन वस्तुतः जिस भूमि पर अवस्थित है वह सुरक्षित वन भूमि न होकर राजस्व अभिलेख में साखु जंगल के रूप में वर्णित है। झारखण्ड सरकार, लोक कार्य (पथ एवं भवन) तथा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं०-254(s) तदनुसार ज्ञापांक-255(s) दिनांक-23.01.2001 द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका के आवास को माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड राज्य के दुमका में अस्थायी

शिविर आवास के रूप में परिणत किया गया। (छायाप्रति संलग्न) तदोपरांत इसे राज्य भवन में परिणत किया गया। चूंकि यह भवन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने के पहले बना था, अतः इसे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं समझा जाना उचित होगा। तथापि इस भवन से संबंधित भूमि को वनभूमि मानते हुए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत अपयोजन प्रस्ताव प्राप्त है।

3. **मजिस्ट्रेट कॉलोनी, पुलिस उप महानिरीक्षक का आवास तथा पुलिस लाईन**— सर्वे कार्य में निपुण वन कर्मियों की कमी थी। स्थापित वनकर्मियों की कमी के कारण उक्त निर्माण को संज्ञान में देर से लिया गया होगा। विस्तृत सर्वे कार्य के उपरांत जब उक्त वन भूमि पर अतिक्रमण प्रकाश में आया, जिससे ज्ञात हुआ कि मजिस्ट्रेट कॉलोनी तथा आरक्षी उप महानिरीक्षक आवास एवं पुलिस लाईन का अंश अधिसूचित वन भूमि पर निर्मित था। चूंकि इन भवनों के निर्माण के संबंध में प्रमंडलीय कार्यालय में कोई पुष्ट अभिलेख उपलब्ध नहीं था, अतः संबंधित पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि संभवतः मजिस्ट्रेट कॉलोनी 1990 के दशक में तथा इसके कुछ बाद संभवतः DIG Residence तथा पुलिस लाईन का निर्माण हुआ। मजिस्ट्रेट कॉलोनी के संबंध में इस कार्यालय द्वारा 2005 में उपायुक्त को संबंधित पत्र में उल्लेख किया गया है, जिसमें लिखा गया कि उक्त निर्माण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन किया गया था। तदोपरांत इस कार्यालय के द्वारा वर्ष 2007 में उपायुक्त को लिखे गए पत्र में मजिस्ट्रेट कॉलोनी, पुलिस उप महानिरीक्षक आवास तथा पुलिस लाईन के निर्माण का उल्लेख है, जिसमें उपायुक्त, दुमका को लिखा गया था कि उपरोक्त तीनों संरचनाएँ वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन में किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत स्वीकृति हेतु जिला प्रशासन/कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण, भवन प्रमंडल, दुमका को इस कार्यालय के पत्रांक-1375 दिनांक-18.4.2002, 2450 दिनांक-06.10.2005, 1687 दिनांक-17.7.2007, 2751 दिनांक-21.11.2007, 2325 दिनांक-03.8.2016, 2335 दिनांक-04.8.2016, 3232 दिनांक-12.11.2016, 231 दिनांक 18.01.2017, 277 दिनांक 25.01.2017, 417 दिनांक 08.02.2017, 709 दिनांक 04.3.2017 1225 दिनांक 08.4.2017, 1379 दिनांक 27.4.2017 द्वारा अतिक्रमित वनभूमि के अपयोजन हेतु प्रस्ताव समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया। तदोपरांत कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण, भवन प्रमंडल, दुमका का पत्रांक-268 दिनांक-26.02.2018 द्वारा Online वनभूमि अपयोजन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है। जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत प्रावधान उपलब्ध है। चूंकि वन विभाग के कर्मचारी/पदाधिकारी द्वारा मामला स्वतः संज्ञान में आते ही कार्रवाई काफी पहले की गई एवं उक्त सभी भवनों के निर्माण की तिथि संबंधी सूचना वन प्रमंडल कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। अतः अभिलेख के अनुसार वन पदाधिकारी/कर्मचारियों के संलिप्तता की पुष्टि नहीं होती है। इस कार्यालय के पत्रांक-229 दिनांक-19.01.2018 तथा 538 दिनांक-08.02.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्माण संबंधी समय/वर्ष एवं पदाधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं वन संरक्षण के उल्लंघन संबंधी सूचना की मांग की गई है। सूचना उपलब्ध होने के पश्चात् प्रतिवेदित किया जायेगा।

अनु0-यथोक्त

विश्वासभाजन,

30/06/18

वन प्रमंडल पदाधिकारी,

दुमका वन प्रमंडल, दुमका।

FORM-II

(for project other than linear projects)

Government of Jharkhand**Office of the District Collector Dumka****(Corrected Letter)**

No./

Dated2018

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **38.21 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Magistrate Coloney, DIG Residence, Police Line, Outdoor Stadium, SP Mahila College Hostel (name of user agency) in **Dumka** district falls within jurisdiction of Bandarjori village(s) in **Dumka** tehsils. Detail of Land noted below :-

Sl. No	Date of Gram sabha	Rev. Vill	Thana No	Khata No	Plot No	Land/Area Acre/Dismil		Total Area (in Acre/Dismil)
						Notified Forest	Shakun Jungle/ Demarcated Forest	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	30.08.2017 25.01.2018	Magistrate Coloney	-	36	472 350	17.76	0 0	17.76
2		DIG Residence	-	76	456	3.05	0	3.05
3		Police Line	-		350/P	2.15	0	2.15
4		Outdoor Stadium	-		364	7.00	0	7.00
5		Rajbhawan	-		13,14/P, 317	0	5.17	5.17
6		Mahila College Hostel	-		03/P	3.08	0	3.08
Total :-						33.04	5.17	38.21

It is further certified that

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **38.21** of forest land proposed for diversion. Acopy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to... Annexure
- the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and

details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Bandarjori villager(s) is enclosed as annexure -01

- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present,
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl... As above

Efor
District Collector
Dumka

Memo No. 735...../(Wel), Dated. 20-06-2018.

Copy To :-

1. Additional Collector, Dumka for information and necessary action.
2. Divisional Forest Officer, Dumka, for information and necessary action.
3. Commissioner S.P. Division , Dumka for kind information.
4. Special Secretary to Government Revenue and Land Reform Deptt. Jharkhand, Ranchi for information.
5. Tribal Welfare Commissioner, Jharkhand, Ranchi for kind information.

24/6/18
District Collector
Dumka

आज दिनांक 25.01/18 को पंचायत बन्दरजोरी भवन

में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें
वेकन की अध्यक्षता सुविधा जी पुन मर्यादा
के द्वारा की जा रही है। आज के ग्राम सभा में वन अधिकारी
अधिकारम 2006 के तहत वन भूमि में जमीन को पहा
के माध्यम से हस्तान्तरण करने के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है।

उपस्थित
मुखिया

उपस्थित ग्रामीणों का हस्ताक्षर एवं वीप निम्न

- 1) 2 प्रमोद चाना
- 2) वरुणा देवी
- 3) प्रमिला देवी
- 4) गणेश चक्र
- 5) रोमा देवी
- 6) रेशनी मुख
- 7) लक्ष्मीराम मशरु
- 8) सरजू चालक
- कालू चालक
- सुनील चालक

Akshay kumar

राजेश कुमार

सुनील

सुनील

सुनील

प्रमोद

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਲਕੁ

ਆਮ ਪਾਲਕ

ਮਿਸਟਰ ਪਾਪੋਦ

ਮੁਕਤ ਭਾਗ

ਪੁਲਾ ਮੰ 5 ਦਾਸ

2 ਲੇ-3 ਦਾਸ

ਮੁਕਤ ਭਾਗ

ਅਮਰ ਰੇਖਾ

ਸੰਸਦ ਫੀ

ਆਪਣਾ ਦਾਸ

ਮਿਲਿਪੁਰੀ

ਮਿਲਿਪੁਰੀ

ਮੇਮੋਲ ਚਾਕਕ

ਆਕਾਸ਼ ਚਾਕਕ

ਆਮ ਚਾਲਕ

ਮਹਲਕ

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਾਕਕ

2 ਦਾਸ ਮੰ 5 ਦਾਸ

ਫੰਡ ਮਾ ਚਾਕਕ

ਮੁਕਤ ਭਾਗ

ਮਿਲਿਪੁਰੀ

ਮਿਲਿਪੁਰੀ

ਮਿਲਿਪੁਰੀ

ਮਿਲਿਪੁਰੀ ਮਿਲਿਪੁਰੀ 25/01-2018 ਦੇ ਆਮ ਚਾਕਕੀ ਚਾਕਕ
ਨੰ 12 ਦੇ ਆਮ ਚਾਕਕੀ ਚਾਕਕੀ ਦੇ ਆਮ ਚਾਕਕੀ ਚਾਕਕੀ ਚਾਕਕੀ
ਮੁਕਤ ਭਾਗ ਮੁਕਤ ਭਾਗ ਮੁਕਤ ਭਾਗ ਮੁਕਤ ਭਾਗ ਮੁਕਤ ਭਾਗ
ਮੁਕਤ ਭਾਗ ਮੁਕਤ ਭਾਗ ਮੁਕਤ ਭਾਗ ਮੁਕਤ ਭਾਗ ਮੁਕਤ ਭਾਗ
ਮੁਕਤ ਭਾਗ ਮੁਕਤ ਭਾਗ ਮੁਕਤ ਭਾਗ ਮੁਕਤ ਭਾਗ ਮੁਕਤ ਭਾਗ

नौआ कुल्ही कुड़प रीयाक सीमवीध के कुकस जीते
सैर आकन होड ताला रे होयेना। जे वंदरजोरी जाते
रे वन भूमि राखा वीर रे लाहा, रवान वैनाल आकन
सरकारी ओड़ाक गार्क टंडी उमान तिपाक जाफना। वीकी
सते इराक जाते उमीक रेयाक काना। ओना रघीत कुल्ही
कुड़प से राम सभा रे जाफवा आकन होड को दो को रानी
गिपा।

उना वाक कुल्ही कुड़प से राम सभा रे जाते
होड राजी कुल्ही ते को गोरा के दा जे राम वन अधिकाप
समिति बनाव जासके काना जे मीन लाहा रेयाक कामी होय
दाडेयाक।

वंदरजोरी जाते रे वन अधिकाप समिति गोठेन
हुयना आर नौआ समिति रेन सदस्य को रेयाक चपन
जोते होड राजी कुल्ही ते हुयना। नौआ समिति रेन सदा
वाक नुतुम आर दोसरवोत को लागप रे मेनाक।

राम सभा के बैठक में उद्देश्य के संवेध से चर्चा
किया गया कि मौजा वंदरजोरी में अवस्थित वन भूमि।
राखा जंगल में हरे से निर्मित सरकारी भवनें खेस सैदान
होनाक वना हुआ है। उक्त वन भूमि के जमीन का अपभोग
किया जाना है। इसके लिए राम सभा द्वारा विचार-विमर्श
करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राम
वन अधिकाप समिति का विधिवत गठन किया जाए ताकि
आगे का कार्यवाही किया जा सके।

मौजा वंदरजोरी में राम वन अधिकाप समिति का
गठन हेतु सदस्य गण का चुनाव सर्व सम्मति से किया
गया जो निम्न प्रकार है: —

ક્રમાંક

નામ

પદનામ

①	અક્ષય લુમાર	અક્ષય
②	વરરા વિરજુ	સચિવ
③	લોહાની મુર્મી	"
④	વિશાલ હરિ	"
5.	અર્જુન રાજાવ	"
6.	સીતા મરંડી	"
7.	વેરવા સોરેન	"
⑧	મુન્નિયા મુર્મી	"
⑨	સોનામુની હેમ્લમ	"
10.	ટીકા સોરેન	"
11.	બાલુલાલ મરંડી	"
12.	રામેશ્વર વિરજુ	"
13.	અક્ષય લુમાર	"
14.	રાજેશ મેડલ	"
15.	ગૌતમ ચાલક	"

મોજા વંદરજોડી મેં વન સ્થળ પર અવરોધ સરના
મવન / રહેલ મેદાન ના વિવરણી નિમ્ન અપાઈ છે -

વંદરજોડી અગ્રે રે વન સ્થળ રે વનાવ આવાન સરના
અગ્રે રે રાજે રે જોલ આવાના

કુલ સરજો
મુલ

ગ્રામ પંચાયત વંદરજોડી
જિલ્લા દમકા

क्र०	अंचल का नाम	प्रतिशत प्रतिशत	मौजा का नाम	रकबा स.	रकबा स.	अधिकारिता प्राप्त करने की तिथि	उपभूक्त भू-भाग की रकबा	अंश	रकबा स.	रकबा स.	रकबा स.	रकबा स.	रकबा स.
1	कुम्भा	मौजा रोड कांटेरी	वन्दार	76	472	10.40	7.41	1/12/18					
					350	7.50	1.72	"					
2	कुम्भा	पुलिस उप मंच निजीकरण का जवाब	वन्दार जेरी	76	456	3.05	2.02	2/1/19					
3	कुम्भा	पुलिस लाईन	"	76	350 P	2.15	0.81	3/1/19					
4	कुम्भा	आपडोप स्टेडियम	"	76	364	7.00	2.99	4/1/19					
5	कुम्भा	राजमन	"	76	13.14 P 317	4.96	5.17	5/1/19					0.21A सिलव रकबा
6	कुम्भा	महिला भवन विद्यालय सह छात्रावास	"	76	311	3.08	3.08	6/1/19					
				3821		2320	15.01						

उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये सरकारी भू-भागों के क्षेत्र क्षेत्र में जमीन जो वन भूमि का उक्त वन भूमि का अपभोजन लोकोपकारी कार्य किया जाना है। इसलिए राजा क्षेत्र राजा वन - बर्खास्त समिति के द्वारा जारी किया गया है, कि हम लोगों को किसी प्रकार का आपत्त नहीं है।

वेदान्त जयस अमान

लक्ष्मण

66

~~67~~

~~68~~

6

1

सरकारी - जोड़ा - आप गाँव हाँडी
 से जान जाया जोका दो वन हमि रे पा
 जाना। जोना वन हमि रे दो जोड़ा बि
 लागि ते सरकारी जोड़ा। गाँव हाँडी वेना
 आना। जोना लुलसी दुइप से राम
 सभा आप जोना वन जलियाप सीमी
 दो नोआ प्रसाव लागि ते राजी जिना जल
 आपि वनक बाबे।

जान की सभा जलियाप
 द्वारा लुलसी दुइप से गाँव सभा की
 गई।

ते आप लुलसी दुइप दो जलियाप
 सभा सभा जोका सीमी ते मुने इना

राम सभा वंदर जोरी
 जिला दुमका

अध्यापक
 राम वनाधिकार सीमी
 वंदर जोरी दुमका